



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (जसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, १९ सितम्बर, १९९४/२८ भाद्रपद, १९१६

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रसिद्धता

सितम्बर-४, १९ सितम्बर, १९९४

पञ्चा १-५८/९४-वि० एच०—हिमाचल प्रदेश नगर पालिका सेवा विधेयक, १९९४ (१९९४ का विधेयक संख्या १५) को सात दिनांक १९ सितम्बर, १९९४ को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरस्कृतित हो

नया है। वी एन प्रति हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संज्ञासूचि, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत सर्व साधारण सूचनाएँ राजपत्र में मूद्रित करने हेतु प्रेषित की जाती है।

भवदीय,
लक्ष्मण सिंह,
सचिव।

1994 का विधेय संख्या 15

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा विधेयक, 1994

(विधान सभा में पेशा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में नगरपालिका सेवाओं के एकीकरण, अर्थात् और शर्तों तथा उससे संबंधित अन्य मामलों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के संसदीय व्यवस्था में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 है।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह 30 मई, 1994 को प्रवृत्त होगा और प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, —

परिभाषाएं।

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से नगरपालिका सेवाओं में पदों पर नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "सीधी भर्ती" से सेवाओं में से प्रोन्नति द्वारा या पहले ही किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी निगम, बोर्ड या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सेवा के पदधारी के स्थानान्तरण द्वारा से अन्यथा नियुक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "छुट्टी" से अनिवार्य अजित छुट्टी, प्रमूति छुट्टी, वर्जन शोध छुट्टी, अर्ध वेतन पर छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी और अनुशासन छुट्टी है किन्तु अनुशासन छुट्टी इनके अन्तर्गत नहीं है;

(ङ) "रदस्व" से इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य स्तरीय नगरपालिका सेवा बोर्ड का रदस्व अभिप्रेत है;

(च) "नगरपालिका" से स्वशासन की निम्नलिखित संस्था अभिप्रेत हैः—

(क) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का ...) के अधीन गठित नगर पंचायत और नगर परिषद; और

(ख) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का ...) के अधीन गठित नगर निगम;

(ड) "बहिष्कृत" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा बहिष्कृत अभिप्रेत है।

- (ज) नगरपालिका के सम्बन्ध में "सेवा" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में राज्य स्तर पर गठित नगरपालिका सेवा अभिप्रेत है;
- (झ) "सेवा चयन समिति" से इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित समिति अभिप्रेत है।

सेवा का
गठन।

3. (1) राज्य स्तरीय नगरपालिका सेवा में इस अधिनियम की अनुसूची-I में बताए गए पद समाविष्ट होंगे।

(2) सरकार को, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-I में विभिन्न पदनामों और वेतनमानों के पदों में, या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, बढ़ाने या घटाने का अधिकार होगा।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सेवा के संबंध में अनुशासनात्मक मामलों सहित, सेवा की प्रवृत्ति, भर्ती का ढंग, सम्बलन, छुट्टी भत्ता और सेवा की अन्य बातें, ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के अधीन किसी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त किया गया नहीं माना जाएगा।

विद्यमान
कर्मचारियों
का एकी-
करण।

4. (1) हिमाचल प्रदेश राज्य में नगरपालिकाओं के कर्मचारी, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर नियमित तौर पर कार्यरत हैं जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, उस प्रक्रिया के अनुसार सेवा में एकीकृत हो जाएंगे वैसे सरकार द्वारा अधिकारित की जाए।

(2) सेवा के सदस्य के उस मूल वेतन में कमी नहीं की जाएगी जो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्राप्त कर रहा था, किन्तु कोई विशेष वेतन जो सेवा का सदस्य किसी अतिरिक्त कर्तव्य के लिए प्राप्त कर रहा था, सुरक्षित नहीं किया जाएगा।

(3) उप-धारा (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना सेवा के किसी सदस्य का वेतन, अनुसूची-I में सम्मिलित पद के वेतनमान में, राज्य सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू मूल नियमों के अनुसार समायोजित और निश्चित किया जाएगा।

नगरपालिका
सेवाओं का
सरकार द्वारा
अधिकार में
लेने की
शक्ति।

5. (1) इस अधिनियम, किसी अन्य प्रवृत्ति विधि, के तदधीन बनाए गए नियमों और विस्तारित सविदाओं और किए गए प्रावधानों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार, यदि यह उचित समझे कि ऐसा करना समर्थ और आवश्यक है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट नगरपालिका में कार्यरत सभी या कर्मचारियों के किसी वर्ग को अपने अधिकार में ले सकती।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कर्मचारियों के किसी वर्ग को अधिकार में लिया जाता है वहां ऐसे कर्मचारी सरकार के कर्मचारी बन जाएंगे और ऐसे पारिश्रमिक क हकदार होंगे और ऐसे नियमों और विनियमों से शासित होंगे जैसे राज्य सरकार के समतुल्य पदों के कर्मचारियों को लागू हैं।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कर्मचारियों के किसी वर्ग को राज्य सरकार द्वारा अधिकार में लिया जाता है, वहां उनका विलय सरकार के उस विभाग के

कर्मचारियों में किया जाएगा, जिस को सरकार आदेश दे :

परन्तु जहाँ ऐसे कर्मचारी नगरपालिका से इस प्रकार अधिकार में लिए जाते हैं, वहाँ नगरपालिका में तत्स्थानी पद सरकार के सम्बन्धित विभाग के संवर्ग में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे और वेतन और भत्ते आदि के कारण खर्च सम्बन्धित नगरपालिका द्वारा वहन किया जाएगा ।

(4) कर्मचारियों के ऐसे वर्ग द्वारा, ऐसी सेवा को अधिकार में लेने से पूर्व नगरपालिका के अधीन की गई कोई सेवा, राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा समझी जाएगी :

परन्तु जहाँ सरकार द्वारा उप-धारा (1) के अधीन कर्मचारियों को किसी वर्ग का अधिकार में लिया जाता है वहाँ वे कर्मचारी जिनकी सेवाओं को अधिकार में लिया गया है, सरकारी कर्मचारियों को यथा लागू किए गए पेन्शन विनियमों द्वारा शासित होंगे, परन्तु यह तब जबकि वे अभिदायी भविष्य निधि के अपने अभिदाय को इसमें ब्याज सहित अन्तर्भूत करने के विकल्प का प्रयोग करें और वह राजि राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग में उनके सामान्य भविष्य निधि में जमा की जाएगी और नगरपालिका का अंशदान, उस पर ब्याज सहित, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में जमा किया जाएगा ।

(5) उप-धारा (1) से (4) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी भी ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगी, जो इस प्रकार अधिकार में लिए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर राज्य सरकार का कर्मचारी न बनने के अपने विकल्प की राज्य सरकार को उस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा सूचना देता है, और जहाँ कोई कर्मचारी ऐसा नोटिस देता है, वहाँ नगरपालिका के अधीन उसकी सेवा ऐसे अधिकार में लिए जाने की तारीख से समाप्त हो जाएगी और वह नगरपालिका से प्रतिरुत का हकदार होगा, जो निम्नलिखित होगा :—

(क) स्थायी कर्मचारी के मामले में, उसके तीन मास या उसके बाकी सेवा की अवधि के वेतन (भत्तों सहित) के बराबर राजि, जो भी कम हो;

(ख) अस्थायी कर्मचारी के मामले में, उसके एक मास या उसकी सेवा की बाकी अवधि के वेतन (सभी भत्तों सहित) के बराबर राजि जो भी कम हो ।

6. (1) उप-धारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाए, सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती करने के लिए परीक्षाओं का संचालन तथा साक्षात्कार लेने के लिए गठित सेवा चयन समिति को सिफारिश पर की जाएगी ।

सेवा में
भर्ती ।

(2) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित नियुक्तियों के लिए लागू नहीं होगी—

- (i) हिमाचल प्रदेश नगरनियम अधिनियम, 1994 की धारा 45 और 46 के अधीन आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और सहायक आयुक्तों,
- (ii) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 305 के अधीन नगरपालिका परिषद् के कार्यपालक अधिकारी और नगर पंचायत के सदस्य, और

- (iii) छ: मास से अधिक अवधि के लिए पदों पर सेवा में प्रोन्नति और
 (iv) धारा 5 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकार में ली गई सेवाएं।
 परिवीक्षा। 7. (1) सेवा में नियुक्त किया गया व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

- (क) ऐसी नियुक्ति के पश्चात् तत्स्थानी या उच्चतर पद पर प्रतिनिधिक पद व्यक्ती की गई कोई अवधि परिवीक्षा अवधि में संगणित की जाएगी; और
 (ख) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यक्ती की गई अवधि के रूप में मानी जाएगी, किन्तु कोई व्यक्ति जिसने स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, तब तब स्थायीकरण का हकदार नहीं होगा, जब तक उसे किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त नहीं किया जाता है।
 (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान कार्य या आचरण सन्तोषप्रद नहीं हो, तो वह,—

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधा भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है उसे सेवा से अलग कर सकेगा;
 (ख) यदि ऐसा व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया है,—
 (i) उसे अपने पूर्ववर्ती पद पर प्रतिर्वात कर सकेगा, या
 (ii) उसके विरुद्ध ऐसी रीति में कार्रवाई कर सकेगा जैसी पूर्व नियुक्ति के नियन्धन और शर्त अनुज्ञात करें; या
 (iii) उसकी परिवीक्षा अवधि में विस्तार करेगा; और तत्पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा जो इसने परिवीक्षा की प्रथम अवधि के अन्तर्गत पर पारित किए होते :

परन्तु विस्तार सहित, यदि कोई हो, परिवीक्षा की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी यदि उसकी राय में, उसका कार्य और आचरण सन्तोषप्रद रहा है तो—

- (i) ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तारीख से स्थायी कर सकेगा यदि स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, या
 (ii) यदि स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस तारीख से स्थायी कर सकेगा जिसको स्थायी रिक्ति होती है, या
 (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो यह घोषित कर सकेगा कि उसने अपनी परिवीक्षा सन्तोषप्रद रूप से पूरी कर ली है।

स्थानान्तरण— 8. राज्य स्तरीय नगरपालिका सेवा का कोई सदस्य हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी का दायित्व भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा।

9. सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वारिष्ठता, प्रत्येक वर्ग के लिए उक्त वर्ग में किसी वारिष्ठता। पद पर उनके लगातार-सेवाकाल द्वारा, पृथक्-अवधारित की जाएगी :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनका पारस्परिक वारिष्ठता, यथास्थिति, सेवा चयन समिति या किसी प्राधिकारी द्वारा अवधारित गुणागुण के क्रम में होगी :

परन्तु यह और कि एक ही तारीख को नियुक्त दो या अधिक सदस्यों की दशा में, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य अन्यथा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा।

10. (1) सेवा का प्रत्येक सदस्य इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा यथा विहित प्राधिकारी द्वारा किन्हीं विभागीय नियमों/विनियमों या अनुशासन के अंग अथवा असाधारण, अनुपयुक्तता, दत्तव्य उपेक्षा, पद अवधारण के लिए, उसकी वेतन वृद्धि या प्रोन्नति रोकने, परिनिष्ठा की जाने, पंक्ति में अवतरत किए जाने, अनिवार्यतः निवृत्त, प्रतिवर्तित या पदच्युत किए जाने के लिए दायी होगा :

दण्ड और अपील।

परन्तु, यथापूर्वोक्त, सेवा के किसी सदस्य को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पंक्ति अवतरत, अनिवार्यतः निवृत्त, हटाया या पदच्युत नहीं किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सेवा के किसी सदस्य को तब तक दण्डित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके विरुद्ध की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध उसे कारण दर्शात करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह उप-धारा वहां लागू नहीं होगी,—

- (क) जहां सेवा के किसी सदस्य को ऐसे आचरण के आधार पर पद से हटाया जाता है या पदच्युत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर उसे दोषसिद्ध किया गया है; या
- (ख) जहां सेवा के ऐसे सदस्य को पद से हटाने या पदच्युत करने के लिए तत्पक्ष प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसे कारणों से, जो उन प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, यह युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है कि उस व्यक्ति को कारण दर्शात करने का अवसर दिया जाए; या
- (ग) जहां राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में सेवा के सदस्य को कारण दर्शात करने का अवसर देना समीचीन नहीं है;
- (घ) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या उप-धारा (2) के अधीन सेवा के सदस्य को कारण दर्शात करने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से साध्य है या नहीं, तो उसे पद से हटाने या पदच्युत करने के लिए तत्पक्ष प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) सेवा का वह सदस्य, जिसे इस धारा के अधीन दण्डित किया गया है, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो, विहित किया जाए।

(4) सेवा के किसी वर्ग के पदों के बारे में शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाएं।

(5) हिमाचल प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को यथा लागू और समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) और केन्द्रीय सिविल सेवा (प्राचरण) नियमों सहित केन्द्रीय सिविल सेवा नियम जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन गठित सेवाओं के सदस्यों को लागू होंगे।

सेवा से
त्यागपत्र।

11. यदि सेवा का कोई सदस्य सेवा से त्याग-पत्र देना चाहता है, तो वह नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास का लिखित नोटिस देगा। यदि सेवा का सदस्य ऐसा नोटिस देने में असफल रहता है या लघुतर नोटिस देता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे सदस्य से, नोटिस के बदले में, यथास्थिति, सामान्य भत्तों सहित एक मास का सम्बलन या उस अवधि का जिसके लिए नोटिस एक मास से कम पड़ता है सम्बलन और भत्ते वसूल कर सकेगा।

सेवा निवृत्ति।

12. सेवा के सदस्य उस मास के अन्तिम दिन के अपराह्न, जिस में वे छठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं, को सेवा निवृत्त हो जाएंगे, सिवाय कर्मकार के, जो साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होंगे।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "कर्मकार" से सेवा में मासिक वेतन दर पर नियोजित कुशल, अर्धकुशल या अकुशल कारीगर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कर्मकार के रूप में सरकार द्वारा घोषित बपड़ासी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, माली, रसोईया भी हैं।

परन्तु—

- (i) नियुक्ति प्राधिकारी को यदि उसकी राय में ऐसा करना लोकहित में हो कर्मचारी को लिखित नोटिस देकर, उस कर्मचारी को, उस तारीख का जब वह तीस वर्ष की सेवा या सेवा की ऐसी अवधि पूरी करता है जो राज्य सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए विहित करे अथवा पचपन वर्ष की आयु या ऐसी आयु प्राप्त करता है जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए विहित करे अथवा तत्पश्चात् किसी तारीख को जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी, सेवा से निवृत्त करने का, प्रात्यंतिक अधिकार होगा;
- (ii) ऐसे नोटिस की अवधि एक मास से कम नहीं होगी और यदि कम से कम एक मास का नोटिस नहीं दिया जाता है या एक मास से कम अवधि का नोटिस दिया जाता है, तो कर्मचारी, यथास्थिति, एक मास की अवधि के लिए या उतनी अवधि के लिए, जितनी के लिए नोटिस एक मास से कम है, अपने वेतन और भत्तों की रकम के समतुल्य राशि का उसी दर पर जिस पर वह सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व प्राप्त कर रहा था दावा करने का हकदार होगा;
- (iii) कोई कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम एक मास का पूर्वतन लिखित नोटिस देने के पश्चात् उस तारीख को जिसको वह बीस वर्ष की सेवा या सेवा की ऐसी अवधि पूरी करता है जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए विहित करे या पचास वर्ष की आयु अथवा ऐसी आयु प्राप्त कर लेता है जैसी राज्य सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए

विहित कर या सत्यवाच्य किसी तारीख को जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाएगी, सेवा में सेवानिवृत्त हो सकेगा, किन्तु निम्नलिखित कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी के लिखित विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना, सेवा में सेवानिवृत्त नहीं होगा।

13. (1) सरकार के पूर्व अनुमोदन से, नगरपालिका निम्नलिखित को असाधारण पेंशन या उपदान दे सकेगी—

- (क) अपने कर्तव्य के निर्वहन में घायल किसी कर्मचारी;
- (ख) किसी कर्मचारी, जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में मारा जाता है, के कुटुम्ब को।

(2) असाधारण पेंशन या उपदान उस राशि से अधिक नहीं होगी जिसको सेवा का ऐसा सदस्य या उसका कुटुम्ब हितकार होता है यदि वह राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी था।

असाधारण पेंशन और उपदान।

1925 का 19

14. (1) सेवा का सदस्य, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के अधीन उसे अनुज्ञेय अभिदायी भविष्य निधि प्रविधा के बदले में, सेवा और कुटुम्ब पेंशन का विकल्प दे सकेगा और उन दोनों में वह उन नियमों द्वारा शासित होगा जो राज्य सरकार के कर्मचारियों की भाँति और ऐसा व्यक्ति सामान्य भविष्य निधि में अभिदाय करेगा:

अभिदायी भविष्य निधि के बदले पेंशन।

परन्तु —

(क) नगरपालिका द्वारा ऐसे व्यक्ति के अभिदायी भविष्य निधि में उसके जमा धन का शेयर, उस पर प्रोद्भूत व्याज सहित, इस प्रयोजन के लिए स्थापित पेंशन और उपदान निधि में जमा किया जाएगा;

(ख) ऐसे व्यक्ति के अपने अभिदाय के कारण, अभिदायी भविष्य निधि में उसके जमा धन का शेयर, उस पर प्रोद्भूत व्याज सहित, इस प्रयोजन के लिए स्थापित सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते में अन्तर्गत किया जाएगा और सेवा के दौरान प्रगाहरण से नगरपालिका को हुई किसी हानि की पूर्ति उस द्वारा की जाएगी।

(2) नगरपालिका, सेवा के उन सदस्यों के सम्बन्ध में जिन्होंने उप-धारा (1) के अधीन पेंशन का विकल्प दिया है, पेंशन और उपदान निधि में अपना अभिदाय नियमित रूप से, किन्तु उस मास से आगामी मास की पाँच तारीख के पश्चात् जिससे अभिदाय संबन्धित है, जमा करेगी।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट "पेंशन और उपदान निधि" और "सामान्य भविष्य निधि" निदेशक नगरीय व स्थानीय निकाय, हिमाचल प्रदेश द्वारा ऐसी रीति में स्थापित और रखी जाएगी, जैसी विहित की जाए।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी वे व्यक्ति भी जो 1-4-1992 को किसी नगरपालिका की नियमित सेवा में थे और 30 मई, 1994 से पहले सेवा निवृत्त हो गए हैं, इस अधिनियम के अधीन सेवा और संदेय कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र होंगे, परन्तु यह तब जबकि वे इस धारा के अधीन सेवा और कुटुम्ब पेंशन के लिए विचार्य हैं और निदेशक को ऐसा अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाए, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय का, या नियोजक से उन द्वारा प्राप्त व्याज सहित, इसके निकालने की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक उम्र पर छः प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण व्याज के साथ प्रतिदाय करें।

विभागीय
परीक्षा।

15. सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि सेवा के किन्हीं पदों पर जो विनिर्दिष्ट किए जाएं नियुक्त व्यक्तियों द्वारा, विभागीय परीक्षा पास करना अपेक्षित है जिसके ब्योरे और पाठ्यक्रम और उसे पास करने में अमफल रहने के परिणाम ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

छुट्टी, यात्रा भत्ता, पद-ग्रहण काल, निलम्बन, चिकित्सीय सुविधाएं, फीस और मानदेय तथा अन्य विषय।

16. छुट्टी, यात्रा भत्ता, पदग्रहणकाल, निलम्बन, छुट्टी, चिकित्सीय सुविधाएं, फीस मानदेय, माना किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, वेतन निर्धारण, वेतनवृद्धि देना, दक्षतारोध पार करना, प्रतिनियुक्ति और अन्य विषयों के बारे में जो इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं हैं, सेवा के सदस्य, राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियमों में अन्तर्विष्ट तत्त्वानों उपबंधों द्वारा शासित होंगे :

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को छुट्टी सम्बलम उस नगरपालिका द्वारा संदत्त किए जाएंगे जहां पर वह छुट्टी पर जाने के समय सेवा कर रहा हो :

परन्तु यह और कि स्थानान्तरणाधीन व्यक्ति अपना यात्रा भत्ता और पदग्रहण काल प्रसुविधाएं उस नगरपालिका से लेगा जिस में उसे स्थानान्तरित किया गया है।

सेवा का
अभिलेख।

17. (1) प्रत्येक सदस्य की एक निजी नस्ति रखी जाएगी जिसमें उसकी सेवा से सम्बन्धित सभी कागजात, रिकार्ड, और अन्य दस्तावेज रखे जाएंगे। नस्ति में विशेषतया एक सेवा पुस्तिका होगी जिसमें उसकी जन्म तिथि, नियुक्ति की तारीख से सेवा का इतिवृत्त, वेतन-वृद्धि, प्रोन्नति, पुरस्कार, दण्ड की विशिष्टियां और उसकी जीवन-वृत्ति की अन्य विशेष घटनाएं अन्तर्विष्ट होंगी। सेवा पुस्तिका में लेखा प्ररूप होगा जिसमें आकस्मिक छुट्टी के सिवाए, छुट्टी का पूर्ण रिकार्ड होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन रखी गई सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि, लाल स्पाही से शब्द और अंक दोनों में लेखबद्ध की जाएगी और सेवा के सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और नगर नियम की दशा में, आयुक्त द्वारा, नगरपालिका की दशा में, कार्यपालक अधिकारी द्वारा तथा नगर पंचायत की दशा में, सचिव द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी, और जन्म तिथि की उक्त प्रविष्टि निश्चायक सबूत मानी जाएगी और किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

(3) प्रत्येक सदस्य के लिए गोपनीय नस्ति रखी जाएगी :

परन्तु सरकार, यदि यह ऐसा विनिश्चय करे, इसके अतिरिक्त सदस्यों की छुट्टी, वेतन और सेवा का विहित रीति में केन्द्रीय अभिलेख रखने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जैसी यह आवश्यक समझे।

राज्य निष्ठा
की शपथ।

18. प्रत्येक सदस्य से विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज्य निष्ठा की शपथ ग्रहण करने की अपेक्षा की जाएगी, यदि उसने शपथ पहले ग्रहण न की हो।

भारक्षण।

19. इस अधिनियम की कोई भी बात, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अंग व्यक्तियों या व्यक्तियों की किसी अन्य श्रेणी या वर्ग के

लिए उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य न्यायियों पर प्रभाव नहीं डालेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों की प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

20. मरनाथ, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की अनुसूची-I और II के मदों में से किसी को, जोड़, लोप या फेरफार द्वारा संशोधित कर सकेंगी और जब अनुसूची इस प्रकार संशोधित की जाती है तो ऐसे जोड़, लोप या फेरफार का वही प्रभाव होगा मानो यह इस अधिनियम द्वारा किया गया था ।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।

21. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित किए जाने अपेक्षित हैं या नियमों में उपबंधित किए जाने हैं ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्वधीन होंगे ।

(4) इस धारा के अधीन विरचित सभी नियम विधान मभा के पटल पर रखे जाएंगे ।

22. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व नगरपालिकाओं में प्रवृत्त नगरपालिका सेवाओं से सम्बन्धित किसी अधिनियमिति, नियम, विनियम और उप-विधियों में अन्तर्विष्ट सभी तत्स्थानी उपबन्ध निरसित हो जाएंगे :

व्यावृत्ति ।

परन्तु इस प्रकार निरसित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, या उप-विधियों के अधीन किया गया कोई आदेश या कोई वारंवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी ।

(2) इस अधिनियम की कोई बात, नगरपालिका में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे राज्य सरकार के अधिकारियों और पदधारियों को लागू नहीं होगी ।

23. (1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

1994 के अध्यादेश संख्यांक 4 का निरसन ।

(2) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अध्यादेश, 1994 का निरसन होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या वारंवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची-I

[धारा 3 (1) देखें]

क्रमांक	सेवा का नाम
1	2

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका राज्य स्तरीय सेवाएँ—

1. अधीक्षक ग्रेड-I.
2. अधीक्षक ग्रेड-II.
3. सहायक/लेखापाल ।
4. कर निरीक्षक ।
5. सफाई निरीक्षक ।
6. सर्वेक्षक ।
7. कार्य पर्यवेक्षक ।
8. प्रयोगशाला तकनीकी ।
9. सफाई पर्यवेक्षक ।

अनुसूची-II

[धारा 5(1) देखें]

क्र० सेवा का नाम

सं०

1 2

1. स्वास्थ्य अधिकारी ।
2. अधिशासी अभियन्ता ।
3. सहायक अभियन्ता ।
4. कनिष्ठ अभियन्ता ।
5. मण्डी अधीक्षक ।
6. ड्राफ्टमैन ।
7. सहायक ड्राफ्टमैन ।
8. पटवारी ।
9. वन मण्डल अधिकारी ।
10. परिक्षेत्र अधिकारी ।
11. उप-वन रेंजर ।
12. वन रक्षक ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

समय द्वारा देश में नगरपालिकाओं और नगर निगमों में नगरीय स्थानीय निकायों को मुख्य रूप से सशक्त बनाने और पुनर्जीवित करने की दृष्टि से संविधान (चौहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 अधिनियमित किया गया ताकि वे नगरों और शहरों में नगरीय जनसंख्या की बढ़ रही आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। हिमाचल प्रदेश में प्रवृत्त नगरपालिका विधियों को संवैधानिक संशोधन के अनुरूप बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अध्यादेश, 1994 (1994 का 2) और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अध्यादेश, 1994 (1994 का 3) 30 मई, 1994 को प्रख्यापित किया गया। उपबन्धों में शून्य को दूर करने और नगरपालिका कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार लाने तथा नगरपालिकाओं में स्वच्छ और दक्ष प्रशासन प्रदान करने के लिए उनकी सेवाओं को अस्तबद्ध बनाने के लिए पूरे प्रदेश में नगरपालिका कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए समरूप विधि अधिनियमित करना आवश्यक समझा गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यादेश के प्रख्यापन द्वारा नगरपालिका कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए नई विधि अधिनियमित करना आवश्यक हो गया था।

विषय अतिरिक्त सांख्यिक महत्व का था और विधानसभा सत्र में नहीं हो और जो परिस्थितियाँ विद्यमान थीं उनके कारण हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन आवश्यक कार्रवाई करना आवश्यक हो गया। अतः हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अध्यादेश, 1994 (1994 का 4) 30 मई, 1994 को प्रख्यापित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, (असाधारण) में 30-5-1994 को प्रकाशित किया गया। अब इस अध्यादेश को नियमित अधिनियमित द्वारा प्रतिस्थापित करना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपांतरणों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए है।

जय बिहारी लाल छाबो,
प्रभारी मन्त्री।

शिफाला:

... 19 सितम्बर, 1994.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्ताव में प्रत्यक्षतः वित्तीय भार प्रत्यक्षित नहीं है। तथापि प्रस्तावित विधेयक के अधिनियमित होने पर खण्ड 5 के अधीन नगरपालिका सेवाओं की अधिकार में लेने और खण्ड 14 के अधीन नगरपालिका सेवाओं के लिए "पेंशन और उपदान निधि" तथा "साधारण भविष्य निधि" को निदेशालय स्तर पर बनाए रखने के लिए प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त व्यय, नगरपालिकाओं की निधि से पूरा किया जाएगा। जहाँ तक स्थानीय स्वशासन निदेशालय को सहाय्य बनाने का सम्बन्ध है उस पर राज्य काय में प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये का व्यय प्रावर्ती व्यय और चार लाख रुपये का अनावर्ती व्यय अन्तर्भूत होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 21 राज्य सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। यह शक्तियाँ विधेयक के उद्देश्यों के उचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हैं और सामान्य प्रवृत्ति की हैं। यह शक्ति पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन प्रयोग में लाई जाएगी और बनाए गए नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश

[स्थानीय स्व0 विभाग नस्ति सं0 एन0 एस0 जी0-1-(3) 2/92-III.]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा विधेयक, 1994 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक की विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

उन कारणों के कथन का स्पष्टीकरण जिनसे हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अध्यादेश, 1994 में उपांतरण आवश्यक हुआ (प्रध्यादेश संख्या 1994 का 4)

30 मई, 1994 को प्रख्यापित मूल अध्यादेश में नगरपालिका सेवाओं को अधिकार में लेने तथा उनके राज्य संवर्ग में विलय के लिए उपबन्ध नहीं है। यह देखा गया है कि शोजकल नगरपालिका लोगों को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है लेकिन उनके पास कर्मचारियों बहुत ही कम हैं। उनके आगे प्रोन्नति के अवसरों के अभाव में और लम्बे गतिरोध के कारण, नगरपालिकाओं के पास उनकी स्थापना में प्रशिक्षित, पूर्ण अर्हता प्राप्त और अनुभवी तकनीकी कर्मियों की बहुत कमी है। इस कमी को दूर करने और नगरपालिकाओं के तकनीकी कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिए जहां ऐसा करना संकलित में समीचीन है, राज्य सरकार को उनकी सेवाओं को अधिकार में लेने के लिए सम्मत् करना आवश्यक है। इसलिए खण्ड 5 अन्तःस्थापित किया गया है और खण्ड 6 और 22 का संशोधन किया गया है। मृदुल सम्बन्धी गनतियों को ठीक करने के लिए खण्ड 4 (3) का संशोधन किया गया है। चूंकि नगरपालिका कर्मचारियों को पैगमन सम्बन्धी सुविधाएं 1-4-1992 में दी गई हैं इसलिए उन व्यक्तियों को पैगमन सुविधा देने के लिए, जो 1-4-92 के पत्रात् सेवा निवृत्त हुए हैं, खण्ड 14 (4) का संशोधन किया गया है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 1994.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL SERVICES BILL, 1994

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the integration, recruitment and conditions of municipal services in the State of Himachal Pradesh and other matters connected therewith.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty fifth year of the Republic of India: as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994.

Short title,
extent and
commence-
ment.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall and shall be deemed to have come into force on the 30th day of May, 1994.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "appointing authority" means the authority empowered by the State Government to make appointments to the posts under the municipal services;

(b) "direct recruitment" means an appointment made by selection otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of any State or Central Government or any Corporation, Board or any other local authority under the control of State Government;

(c) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(d) "leave" includes earned leave, maternity leave, leave not due, leave on half pay, medical leave, commuted leave, and extraordinary leave but does not include casual leave;

(e) "member" means a member of the State level municipal service constituted under this Act;

(f) "municipality" means an institution of self-Government,—

(a) a Nagar Panchayat and a Municipal Council constituted under the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994; and

(b) a Municipal Corporation constituted under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994.

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(h) "service" in relation to municipalities means the municipal service constituted in the prescribed manner by the Government at the State level under the provisions of this Act; and

(i) "service selection committee" means the committee set-up by the State Government under section 6 of this Act.

1994

1994

Composition
of service.

3. (1) Municipal State level services shall comprise of the posts shown in the Schedule-I to this Act.

(2) The Government shall have the right of, by a notification published in the Official Gazette, make additions to, or deletion in, the posts in Schedule-I with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

(3) Subject to the provisions contained in the Act, the qualifications, method of recruitment, salaries, leave, allowances and other conditions of service referred to in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained to the contrary in this Act, a person appointed to the service under this Act shall not be deemed to have been appointed to any civil service or post under the State Government.

Integration
of existing
employees.

4. (1) The employees of the municipalities in the State of Himachal Pradesh and working on regular basis on the commencement of this Act, as may be notified by the Government, shall stand integrated in the service according to the procedure as may be laid down by the Government.

(2) There shall be no reduction in the basic pay of the member of the service which he was drawing immediately before the commencement of this Act, however any special pay which such member of the service was receiving for any additional duties shall not be protected.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (2), the pay of a member of the service shall be adjusted and fixed in the scale of pay of the post included in the Schedule-I in accordance with the provisions of the Fundamental Rules, as applicable to the State Government employees.

Power to
take over
municipal
services by
the Govern-
ment.

5. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, any other law inforce, rules made thereunder and contracts excuted and orders made, the State Government if it thinks fit that it is expedient and necessary to do so, may, by notification in the Official Gazette, take over all or any class of employees working in a municipality, specified in the Schedule-II.

(2) Where any class of employees are taken over under sub-section (1), such employees will become the employees of the State Government and shall be entitled to such remuneration and shall be governed by such rules and regulations as are applicable to the employees of the State Government on equivalent post.

(3) Where any class of employees are taken over by the State Government under sub-section (1), they shall be merged with the employees of that Department of the Government to which the State Government may order :

Provided that where such employees are so taken over from a municipality, the corresponding posts in the municipality shall be filled in by deputation out of cadre of the Government Department concerned and the expenditure on account of payment of salary and allowances etc. shall be born by the municipality concerned.

(4) Any service rendered by such class of employees under a municipality before taking over such service shall be deemed to be service rendered under the State Government :

Provided that where any class of employees are taken over by the State Government under sub-section (1), the employees whose services have been taken over shall be governed by the pensionary regulations as made applicable to the Government employees, provided they exercise their option to surrender their contribution of Contributory Provident Fund alongwith interest thereon which amount will be deposited in their General Provident Fund Account in the Department concerned of the State Government, and the share of the municipality alongwith interest thereon shall be credited to the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh.

(5) Nothing contained in sub-sections(1) to (4) shall apply to any employee. who, by notice in writing in that behalf to the State Government within a period of two months from the date of such taking over, intimates his option for not becoming an employee of the State Government. and where any employee gives such notice, his service under the municipality shall stand terminated with effect from such date of taking over, and he shall be entitled to compensation from the municipality, which shall be as follows :—

- (a) in the case of a permanent employee, a sum equivalent to his salary (including allowances) for a period of three months or for the remaining period of his service, whichever is less ;
- (b) in the case of a temporary employee, a sum equivalent to his salary (including all allowances) for one month or for the remaining period of his service, whichever is less.

6. (1) Save as provided under sub-section (2), the recruitment to various posts in the service shall be made on the recommendation of the service selection committee constituted at the State level by the State Government to conduct examinations, and interviews for recruitment to various posts in the service.

Recruitment to the service.

(2) Nothing contained in this section shall apply for the appointment of—

- (i) the Commissioner, Joint Commissioner and Assistant Commissioners under sections 45 and 46 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 ;
- (ii) the Executive Officer of a Municipal Council and the Secretary of a Nagar Panchayat under section 305 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 ;
- (iii) Promotions to the posts in the service for a period not exceeding six months; and
- (iv) municipal services taken over by the State Government under section 5.

of 1994

Probation. 7. (1) A person appointed to any post in a service shall remain on probation for a period of two years:

Provided that—

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ; and
 - (b) any period of officiating appointment shall be reckoned as the period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work, or conduct of a person appointed to any post in the service during the period of his probation is not satisfactory, it may—
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service ;
 - (b) if such person is appointed by promotion,—
 - (i) revert him to his former post ; or
 - (ii) deal with him in such a manner as the terms and conditions of the previous appointment permit ; or
 - (iii) extend his period of probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may, if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory:—

- (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
- (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ;
- (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy.

8. The member of the State level municipal service shall be liable to serve at any place in the State of Himachal Pradesh. Liability to transfer.

9. The seniority *inter-se* of the members of the service shall be determined separately for every category by the length of their continuous service on a post in the said category: Seniority.

Provided that in the case of members appointed by direct recruitment, their *inter-se* seniority shall be in the order of merit determined by the service selection committee or of any authority, as the case may be :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed otherwise.

10. (1) Every member of the service. shall be liable to have his increments or promotion withheld or to be censured, reduced in rank, compulsorily retired, reverted or dismissed for breach of any departmental rules/regulations or of discipline or for carelessness, unfitness, neglect of duty or office misconduct by such authority as may be prescribed by rules made in this behalf: Punishment and appeal.

Provided that no such member of the service, as aforesaid, shall be reduced in rank, compulsorily retired, removed, or dismissed by an authority subordinate to that by which he was appointed.

(2) No member of the service shall be punished under sub-section (1) unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him:

Provided that this sub-section, shall not apply,—

- (a) where a member of service is removed or dismissed on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge ; or
- (b) where the authority empowered to remove or dismiss such a member of the service is satisfied that for such reasons to be recorded by that authority, it is not reasonably practicable to give that person an opportunity of showing cause ;
- (c) where the Governor is satisfied that in the interest of security of the State it is not expedient to give a member of the service an opportunity of showing cause ; and
- (d) if any question arises whether it is reasonably practicable to give a member of the service an opportunity of showing cause under this sub-section the decision thereon of authority empowered to remove or dismiss him, shall be final.

(3) The member of the service upon whom a punishment has been inflicted under this section may, within such time and in such manner, appeal to such officer or authority as may be prescribed.

(4) The authority empowered to impose penalties and the appellate authority in respect of a category of posts in services shall be such as may be prescribed.

(5) The Central Civil Services Rules, including the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules ; and the Central Civil Services (Conduct) Rules, as amended from time to time and made applicable to the employees of the State Government, shall apply to the members of the service, constituted under this Act, so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

Resignation
from service.

11. If the member of the service wishes to resign from service he shall give one month's notice in writing to the appointing authority. If the member of the service fails to give such a notice, or gives a shorter notice, the appointing authority may recover one month's salary with usual allowances or the salary and allowances for the period by which the notice falls short of one month, as the case may be, from such member, in lieu of the notice.

Retirement
from service.

12. Members of the service shall retire on the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty-eight years ; except the workman, who will retire on attaining the age of sixty years.

Explanation.—For the purpose of this section, the expression “workman” means a skilled, semi-skilled or un-skilled, artisan employed on monthly rate of pay in the service and includes a peon, chowkidar, safai karamchhari, mali, cook and other servants declared by the Government to be the workman :

Provided that—

- (i) the appointing authority shall, if it is of the opinion that it is in public interest to do so, have the absolute right, by giving an employee prior notice in writing, retire that employee on the date on which he completes thirty years of service or such period of service as the State Government may prescribe for its employees from time to time or attains fifty-five years of age or such age as the State Government may prescribe for its employees from time to time or on any date, thereafter to be specified in the notice ;
- (ii) the period of such notice shall not be less than one month and in case at least one month's notice is not given or notice for a period of less than one month is given, the employee shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay and allowances, at the same rate at which he was drawing them immediately before the date of retirement, for a period of one month or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month ;
- (iii) any employee may, after giving at least one month's previous notice in writing to the appointing authority, retire from service on the date on which he completes twenty years of service or such period of service as the State Government may prescribe for its employees from time to time, or attains fifty years of age or such age as the State Government may prescribe for its employees from time to time or from any date thereafter to be specified in the notice, but no employee under suspension shall retire from service except with the specific approval of the appointing authority.

Extraordi-
nary pension
and gratuity

13. (1) With the prior approval of the Government the municipality may give extraordinary pension or gratuity—

- (a) to an employee injured in the discharge of his duties ;

(b) to the family of an employee who is killed in the discharge of his duties.

(2) The extraordinary pension or the gratuity shall not exceed the sum to which such member of service or his family would be entitled if he was an employee under the State Government.

19 of 1925 14. (1) A member of the service may, in lieu of the Contributory Provident Fund benefits admissible to him under the Provident Fund Act, 1925, opt for service and family pensions and in that event he will be governed by the rules, as are applicable to the employees of the State Government ; and such a person shall contribute to the General Provident Fund :

Pension in lieu of Contributory Provident Fund.

Provided that—

- (a) the share of money contribution by the municipality along with interest accrued thereon, to the credit of such a person in his Contributory Provident Fund, shall be credited to the Pension and Gratuity Fund ; established for this purpose ;
- (b) the share of money, alongwith interest accrued thereon, to the credit of such a person in the Contributory Provident Fund on account of his own contribution, shall be transferred to his credit in the General Provident Fund established for the purpose ; and any loss caused to the municipality through withdrawals during the service shall be made good by him.

(2) The municipality shall, in relation to the members of the service who have exercised the option for pension under sub-section (1), shall credit its contributions regularly but not later than fifth day of the month following the month to which the contribution relate, into the Pension and Gratuity Fund.

(3) The "Pension and Gratuity Fund" and "General Provident Fund" referred to in sub-section (1), shall be established and maintained by the Director, Urban Local Bodies, Himachal Pradesh in such manner, as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the persons, who were in the regular service of any municipality as on 1st April, 1992 and had retired before the 30th day of May, 1994, provided they opt for service and family pensions under this section, and refund to the Director, within such period as may be specified, the employer's contribution to the Provident Fund including interest received by them from the employer together with simple interest at six percent per annum from the date of its withdrawal till the date of repayment, will also be eligible for service and family pensions payable under this Act.

15. The Government may, by notification, direct that the persons appointed to any post in a service, as may be specified, shall be required to pass a departmental examination, the details and syllabus for which and the consequences for failure to pass it shall be, as may be prescribed by the Government.

Departmental examination.

Leave, travelling allowance, joining time, suspension, medical facilities, fees, and honoraria and other matters.

16. In respect of leave, travelling allowance, joining time, suspension, leave, medical facilities, fees, honoraria, house rent allowance, dearness allowance, fixation of pay, grant of increment, deputation and other matters not expressly provided in this Act, the member of the service shall be governed by the corresponding provisions contained in the rules applicable to the State Government employees:

Provided that leave salary shall be payable to a member of the service by a municipality where he happens to serve at the time of proceeding on leave:

Provided further that a person on transfer shall draw his travelling allowance and joining time benefits from the municipality to which he is transferred.

Record of service.

17. (1) There shall be maintained a personal file for every member in which shall be placed all papers, record and other documents relating to his service. The file shall contain in particular a service book giving the date of birth, history of service from the date of his appointment, particulars of increment, promotion, reward, punishment and all other special events of his career. The service book shall also contain the leave account form showing a complete record of leave except casual leave.

(2) The date of birth shall be recorded in the service book maintained under sub-section (1), in red ink both in words and figures and duly signed by the concerned member of the service and authenticated in the case of the Municipal Corporation by the Commissioner, in the case of Municipal Council by the Executive Officer and in the case of a Nagar Panchayat by the Secretary; and said entry of date of birth shall be deemed to be the conclusive proof and shall not be questioned in any court of law.

(3) A confidential file shall be maintained for each member :

Provided that the Government may, if it so decides, make such arrangements, as it may deem necessary to maintain, in addition, a centralised record of leave, pay and service of members in the manner prescribed.

Oath of allegiance.

18. Every member, unless he has already done so, shall be required to take an oath of allegiance to the Constitution of India as by law established.

Reservations.

19. Nothing contained in this Act shall effect the reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the Government in this regard from time to time

Provided that the total percentage of the reservations so made shall not exceed fifty percent at any time.

20. The Government may, by notification publish in the Official Gazette, amend by way of addition, omission or variation any of the items of the Schedule I and II to this Act, and when the Schedule is so amended, such addition, omission or variation shall have the effect as if it had been made by this Act.

Power to
amend
Schedules.

21. (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to
make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the matters which under the provisions of this Act, are required to be prescribed or to be provided for in the rules.

(3) All rules made under this Act shall be subject to the condition of previous publication.

(4) All rules framed under this section shall be laid on the Table of the Legislative Assembly.

22. (1) All corresponding provisions contained in any enactment, rules, regulations and bye-laws relating to the municipal services in force in the municipalities immediately before the commencement of this Act, shall stand repealed:

Savings.

Provided that any order made or action taken under the Acts, rules, regulations or bye-laws so repealed shall deemed to have been made under the corresponding provisions of this Act.

(2) Nothing contained in this Act shall apply to the officers or officials of the State Government working on deputation basis with a municipality.

23. (1) The Himachal Pradesh Municipal Services Ordinance, 1994 is hereby repealed.

Repeal of
Ordinance
No. 4 of
1994.

(2) Notwithstanding the repeal of the Himachal Pradesh Municipal Services Ordinance, 1994, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

SCHEDULE-I

[See section 3 (1)]

Sl. No.	Name of the Service
1	2

HIMACHAL MUNICIPAL STATE LEVEL SERVICES OF—

1. Superintendents Grade I
2. Superintendents Grade-II.
3. Assistants/Accountants.
4. Tax Inspectors.
5. Sanitary Inspectors.
6. Surveyors.
7. Work Supervisors.
8. Laboratory Technicians.
9. Sanitary Supervisors.

SCHEDULE-II

[See section 5 (1)]

S. No.	Name of Service
1	2

1. Health officers.
2. Executive Engineers.
3. Assistant Engineers.
4. Junior Engineers.
5. Market Superintendents.
6. Draughtsmen.
7. Assistant Draughtsmen.
8. Patwaries.
9. Divisional Forest Officers.
10. Range Officers.
11. Deputy Forest Rangers.
12. Forest Guards.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Constitution (74th Amendment) Act, 1992 has been enacted by the parliament with a view mainly to strengthen and revitalise the Urban Local Bodies in the municipalities and Municipal Corporations in the country, so that they can subserve the growing needs of the Urban population in towns and cities. In order to bring the municipal laws in force in this State of Himachal Pradesh, in line with the Constitution Amendment, the municipal laws have been re-enacted by promulgating the Himachal Pradesh Municipal Ordinance, 1994 (2 of 1994) and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Ordinance, 1994 (3 of 1994) on 30th May, 1994 with a view to avoid vacuum in the provisions and to improve the conditions of services of the municipal employees and to make their services inter-changeable in order to provide a clean and efficient administration in the municipalities, it was considered necessary to enact the uniform law regulating the conditions of service of the municipal employees throughout the State. To achieve this objective, it became necessary to enact the new law to regulate the service conditions of the municipal employees by way of promulgation of an Ordinance.

The matter was of great public importance and the Legislative Assembly was not in session and the circumstances which existed rendered it necessary for the Governor, Himachal Pradesh to take immediate action under clause (1) of article 213 of the Constitution and as such the Himachal Pradesh Municipal Services Ordinance, 1994 (4 of 1994) was promulgated on 30-5-1994 and published in the Extra-ordinary Gazette Himachal Pradesh dated 30th May, 1994. This Ordinance is now required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance with modifications.

JAI BEHARILAL KHACHI,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The 19th September, 1994.

FINANCIAL MEMORANDUM

There is no direct financial implications involved in the proposal. However, proposed Bill when enacted will involved extra-expenditure on account of the taking over the municipal services under clause 5 and also for the administrative infrastructure to be provided at the Directorate level to maintain "the Pension and Gratuity Fund" and "the General Provident Fund" for the municipal services under clause 14. The expenditure on account of taking over of municipal services is to be borne out of the funds of the Municipalities. So far as the strengthening of Local Self Government Directorate is concerned that will involve extra-expenditure to the tune of Rupees three lakhs as recurring expenditure per annum and Rupees Four lakhs non-recurring out of the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 21 of the Bill empowers the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Bill. The powers sought are necessary for the proper implementation of the provisions of the Bill and are of normal character. This power is to be exercised subject to the condition of previous publication and when the rules are made are to be laid on the table of the State Legislative Assembly.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA

(LSG, Department File No. LSG-I-A(3)2/91-III)

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Municipal Services Bill, 1994, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the State Legislative Assembly.

STATEMENT EXPLAINING REASONS NECESSITATING THE MODIFICATION
IN THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL SERVICES ORDINANCE, 1994

(Ordinance 4 of 1994)

The original Ordinance Promulgated on 30th May, 1994, did not contain the provisions for taking over municipal services and their merger in the State cadres. It has been observed that the municipalities in the present day render technical services to the public and have very scanty staff at their disposal. In the absence of avenues of further promotion for them and long stagnations, it is difficult for the municipalities to have trained, well qualified and experienced technical personnels on their establishments. To remove this bottle neck and to improve the service conditions of technical personnels of the municipalities it has become necessary to empower the State Government to take over such services, wherever it is expedient to do so in the public interest. Hence, clause 5 has been inserted and clauses 6 and 22 have been amended. Clause 4(3) has been amended to rectify the printing mistakes. Clause 14(4) has been amended to provide pensionary relief to those persons who have retired after 1-4-1992, as the pensionary benefits stand extended to municipal employees w. e. f. 1-4-1992.